Title: Need to ensure payment of dues to sugarcane growers in Deoria District of Uttar Pradesh.

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद और देवरिया संसदीय क्षेत्र में गन्ना किसानों को जो गन्ना उन्होंने गौरी बाजार, कठकुइयां, पडरौना और सरदार नगर चीनी मिलों को बेचा है, उसका इन मिलों ने भुगतान नहीं किया है। यह भुगतान दो से लेकर चार साल तक का बाकी है। वहां की चीनी मिलें ठीक नहीं चल रही हैं। यह सब मिलें अब निजी क्षेत्र में हैं। गौरी बाजार, कठकुइयां और पडरौना की चीनी मिलें पहले बी.आई.सी. में थीं, अब निजी हाथों में बेच दी गई हैं। बेचते वक्त यह कहा गया था कि किसान के बकाया के भुगतान के लिए ही यह मिलें बेची जा रही हैं, लेकिन भुगतान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। किसानों की स्थिति दयनीय है, क्योंकि गन्ने की खेती ही उस क्षेत्र का आर्थिक आधार है। किस क्षेत्र का गन्ना किस मिल को दिया जाये, यह भी शासन ही तय करता है। किसान अपनी उपज इसी आशा से बेचता है कि उसका दाम मिलेगा और अगर नहीं मिला तो शासन उसके भुगतान के लिए उचित कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हमारे क्षेत्र के किसानों के भुगतान की जिम्मेदारी नहीं ले रही है।

इस समस्या की तरफ मैंने प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन उनका कहना है कि यह मिलें केन्द्र सरकार में कपड़ा मंत्रालय से संचालित होती हैं या निजी क्षेत्र में हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है और उन्होंने देवरिया में २५ सितम्बर को घोषणा की थी कि यह एक गम्भीर समस्या है, जिसका हल बैठ कर निकाला जायेगा।

मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र, खास तौर से देवरिया एवं कुशीनगर के किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाये, जो कि इस समस्या का हल निकाले।